International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में भारत-बांग्लादेश संबंध: चुनौतियाँ एवं रणनीतिक विकल्प

Diksha[1]; Prof. Sanjay Gupta[2]

[1]Assistant Professor, Department of Political Science, Navyug Kanya Mahavidyalaya, Lucknow, India

[2]Professor & Head Department of Political Science University of Lucknow, Lucknow, India

Corresponding Author Email: dikshayadav702@gmail.com

सारांश— भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक संपर्क, जल-संसाधन प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक संबंध और आर्थिक परस्पर निर्भरता दोनों देशों को सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन सीमा प्रबंधन, नदी-जल बँटवारे, व्यापार असंतुलन और राजनीतिक विश्वास से जुड़े प्रश्न द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बनाते हैं। इस बीच बांग्लादेश के साथ चीन के बढ़ते आर्थिक और सामरिक संपर्क ने क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को एक अतिरिक्त आयाम दिया है। अगस्त 2024 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में राजनीतिक विश्वास और कूटनीतिक संवाद से जुड़े प्रश्न अधिक प्रमुखता से सामने आए। प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक एवं दस्तावेज़-आधारित विधि अपनाते हुए अकादमिक शोध, सरकारी आँकड़ों और नीति-विश्लेषणों के आधार पर इन परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। अध्ययन का केंद्रीय तर्क है कि भारत-बांग्लादेश संबंधों को केवल सुरक्षा या चीन के प्रभाव के दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता; इन्हें आर्थिक परस्पर निर्भरता, जल-कूटनीति, राजनीतिक संवेदनशीलता और बांग्लादेश की विदेश नीति में विविधीकरण की आकांक्षा के संयुक्त संदर्भ में देखना आवश्यक है। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि दीर्घकालीन स्थिरता के लिए भारत को सहयोग के लाभों को अधिक समावेशी बनाना होगा, जबकि बांग्लादेश के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण होगा।

मुख्य शब्द: भारत-बांग्लादेश संबंध, चीन, दक्षिण एशिया, भू-राजनीति, जल-कूटनीति

I. प्रस्तावना

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में विशेष स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक संपर्क, भौगोलिक निकटता और आर्थिक संबंधों का लंबा आधार है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत ने उसके निर्माण और प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद द्विपक्षीय संबंधों का विकास हमेशा समान गति से नहीं हुआ। सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार के साथ-साथ सीमा पर होने वाली घटनाएँ, नदी-जल बँटवारे से संबंधित मतभेद, व्यापार असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास जैसे प्रश्न समय-समय पर संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं।

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

वर्तमान दक्षिण एशियाई परिदृश्य में इन संबंधों को केवल दो देशों के बीच के द्विपक्षीय समीकरण तक सीमित नहीं रखा जा सकता। चीन की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी का बढ़ता महत्त्व तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएँ भारत-बांग्लादेश संबंधों को व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ प्रदान करती हैं। चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों को केवल भारत के विरुद्ध किसी रणनीति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। बांग्लादेश के लिए बाहरी साझेदारों का विविधीकरण आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे, रक्षा सहयोग और विदेश नीति में स्वायत्तता से भी जुड़ा है। दूसरी ओर भारत की चिंताएँ केवल चीन की उपस्थिति तक सीमित नहीं हैं; सीमा-सुरक्षा, संपर्क, ऊर्जा, व्यापार और पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक कनेक्टिविटी भी उसके हितों के केंद्र में हैं।

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन ने द्विपक्षीय संबंधों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को बदल दिया। इसके बाद भारत के प्रति सार्वजनिक धारणा, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से संबंधित प्रश्न और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद की निरंतरता चर्चा के प्रमुख विषय बने। हालांकि राजनीतिक तनाव का अर्थ यह नहीं है कि आर्थिक तथा भौगोलिक परस्पर निर्भरता समाप्त हो गई है। व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और जल-संसाधन जैसे मुद्दे दोनों देशों को निरंतर संवाद के लिए प्रेरित करते हैं (Palit, 2024)।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर उपलब्ध साहित्य में चीन की भूमिका, आर्थिक सहयोग, जल-विवाद और राजनीतिक परिवर्तनों का अलग-अलग अध्ययन किया गया है। फिर भी इन कारकों को एक साथ रखकर यह समझने की आवश्यकता बनी हुई है कि बदलते क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन और बांग्लादेश की घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता कैसे बनाए रखी जा सकती है। प्रस्तुत अध्ययन इसी प्रश्न को केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य भारत-बांग्लादेश संबंधों की प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना और उन रणनीतिक विकल्पों की पहचान करना है जिनके माध्यम से दोनों देश सहयोग को बनाए रख सकते हैं।

इस अध्ययन का प्रमुख शोध-प्रश्न है: चीन की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका और बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन के बीच भारत-बांग्लादेश संबंधों में स्थिरता और विश्वास को किन उपायों से मजबूत किया जा सकता है? अध्ययन का तर्क है कि इन संबंधों का भविष्य केवल बाहरी शक्ति-प्रतिस्पर्धा से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों देश व्यापार, जल-संसाधन, सीमा-सुरक्षा और राजनीतिक संवाद से जुड़े मुद्दों को किस प्रकार प्रबंधित करते हैं।

II. शोध-पद्धति और विश्लेषणात्मक आधार

यह अध्ययन गुणात्मक तथा दस्तावेज़-आधारित विधि पर आधारित है। इसमें अकादमिक शोध-पत्रों, सरकारी व्यापार आँकड़ों और क्षेत्रीय मामलों पर प्रकाशित नीति-विश्लेषणों का उपयोग किया गया है। स्रोतों का चयन भारत-बांग्लादेश संबंधों, चीन की क्षेत्रीय भूमिका, आर्थिक परस्पर निर्भरता, जल-विवाद और अगस्त 2024 के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों से उनकी प्रासंगिकता के आधार पर किया गया है।

अध्ययन का विश्लेषणात्मक आधार तीन परस्पर संबंधित आयाम हैं—आर्थिक परस्पर निर्भरता, रणनीतिक हेजिंग और जल-कूटनीति। आर्थिक परस्पर निर्भरता का दृष्टिकोण यह समझने में सहायक है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यापार, ऊर्जा और संपर्क संबंध दोनों देशों को सहयोग के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। रणनीतिक हेजिंग की अवधारणा बांग्लादेश की उस विदेश नीति को समझने में उपयोगी है जिसमें वह भारत और चीन जैसे महत्त्वपूर्ण साझेदारों में से किसी एक पर पूर्ण निर्भरता से बचते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। भारत-चीन प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बांग्लादेश की स्थिति को समझने के लिए यह दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रासंगिक है (Al Amin, 2025; Rahman, 2025)।

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

जल-कूटनीति का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि साझा नदियों से संबंधित प्रश्न केवल तकनीकी विषय नहीं हैं, बल्कि वे खाद्य सुरक्षा, स्थानीय आजीविका, पर्यावरणीय स्थिरता और राजनीतिक विश्वास से भी जुड़े हैं। इन तीनों आयामों को संयुक्त रूप से देखने से भारत-बांग्लादेश संबंधों की चुनौतियों और संभावित समाधानों का अधिक व्यापक आकलन किया जा सकता है।

अध्ययन की एक सीमा यह है कि यह मुख्यतः उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसलिए इसके निष्कर्ष प्रकाशित शोध, सरकारी आँकड़ों और नीति-विश्लेषणों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसे दोनों देशों की सरकारों की आंतरिक नीति-निर्माण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष विवरण नहीं माना जाना चाहिए।

III. बदलता क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन और चीन की भूमिका

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति ने क्षेत्रीय राजनीति को अधिक जटिल बनाया है। बांग्लादेश के लिए चीन बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, औद्योगिक विकास और रक्षा-संबंधी सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है। चीन की भागीदारी को परिवहन, ऊर्जा, औद्योगिक परियोजनाओं और अन्य विकास संबंधी गतिविधियों के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। दूसरी ओर भारत बांग्लादेश के लिए भौगोलिक निकटता, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय संपर्क के कारण महत्त्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।

इन परिस्थितियों में बांग्लादेश की विदेश नीति को किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण संरेखण के बजाय अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के अनुरूप विकल्प बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। Rahman (2025) भारत और चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों को क्षेत्रीय संदर्भ में रखते हुए संतुलन, रणनीतिक हेजिंग और विदेश नीति की स्वायत्तता से जुड़े प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार Al Amin (2025) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन-भारत प्रतिस्पर्धा के बीच बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह बांग्लादेश के चीन के साथ आर्थिक सहयोग को स्वतः भारत-विरोधी कदम के रूप में न देखे, लेकिन उन परियोजनाओं और व्यवस्थाओं के रणनीतिक प्रभावों का आकलन भी करता रहे जो उसके सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश के लिए आवश्यक है कि वह बाहरी निवेश और रक्षा-सहयोग से मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता, ऋण-संबंधी जोखिमों और अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता के संदर्भ में करे।

चीन की भूमिका भारत-बांग्लादेश संबंधों में प्रतिस्पर्धा का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की पूरी व्याख्या केवल इसी आधार पर नहीं की जा सकती। दोनों देशों के अपने प्रत्यक्ष हित, घरेलू राजनीतिक परिस्थितियाँ और सहयोग की आवश्यकताएँ भी संबंधों की दिशा निर्धारित करती हैं। इसलिए भारत की रणनीति केवल चीन के प्रभाव को सीमित करने तक केंद्रित रहने के बजाय बांग्लादेश के साथ अपने सहयोग को अधिक विश्वसनीय, पारस्परिक और दीर्घकालीन बनाने पर आधारित होनी चाहिए।

बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप का प्रश्न क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की संवेदनशीलता को भी सामने लाता है। हालाँकि, द्वीप को अमेरिका को सौंपे जाने संबंधी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी (AFP, 2024)। इसलिए इस मुद्दे को स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक महत्त्व के संदर्भ में देखना अधिक उचित होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच इस क्षेत्र में पारदर्शी संवाद क्षेत्रीय विश्वास को मजबूत कर सकता है।

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

IV. आर्थिक परस्पर निर्भरता और व्यापार असंतुलन

भारत और बांग्लादेश के संबंधों में व्यापार तथा आर्थिक संपर्क की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश को कपास, खाद्य पदार्थों, मशीनरी और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति करता है, जबकि बांग्लादेश से भारत को वस्त्र, परिधान तथा अन्य उत्पादों का आयात होता है। इस व्यापार से दोनों देशों को लाभ मिलता है, लेकिन व्यापार के आकार और दिशा में अंतर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को लेकर बांग्लादेश में व्यापार-असंतुलन और भारतीय बाजार तक पहुँच से संबंधित चिंताओं का एक कारण रहा है।

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2024 में संसद में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात लगभग 11.065 अरब अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश से आयात लगभग 1.844 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस आधार पर कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12.909 अरब अमेरिकी डॉलर तथा भारत का व्यापार-अधिशेष लगभग 9.221 अरब अमेरिकी डॉलर था (Ministry of Commerce and Industry, Government of India, 2024)। ये आँकड़े व्यापार की दिशा में असमानता को स्पष्ट करते हैं, हालांकि व्यापार-अधिशेष अपने आप में द्विपक्षीय संबंधों की समग्र गुणवत्ता का पूर्ण माप नहीं है।

इस असंतुलन को कम करने के लिए केवल भारत से आयात घटाने की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं होगा। बांग्लादेश के निर्यात आधार का विस्तार, सीमा पर प्रक्रियाओं का सरलीकरण, गैर-शुल्क बाधाओं में कमी और उत्पादन-आधारित सहयोग को बढ़ावा देना अधिक व्यावहारिक उपाय हैं। भारत के लिए बांग्लादेशी उत्पादों को अपने बाजार में अधिक अवसर उपलब्ध कराना और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाना आर्थिक सहयोग को अधिक संतुलित बना सकता है।

परिवहन और संपर्क परियोजनाएँ भी इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। रेल, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाहों तक पहुँच से व्यापार की लागत कम हो सकती है तथा पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन इन परियोजनाओं की दीर्घकालीन सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उनके लाभ स्थानीय उद्योगों, सीमावर्ती समुदायों और दोनों देशों के व्यापारियों तक किस सीमा तक पहुँचते हैं। यदि आर्थिक सहयोग के लाभ असमान रूप से वितरित होते हैं,तो इससे असंतोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

इसलिए आर्थिक संबंधों को केवल व्यापार की कुल मात्रा से नहीं, बल्कि बाजार तक पहुँच, रोजगार, स्थानीय उत्पादन और दोनों देशों के लिए उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण आर्थिक सहयोग को अधिक टिकाऊ बनाने और राजनीतिक संबंधों के लिए सकारात्मक आधार तैयार करने में सहायक हो सकता है।

V. जल-विवाद, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा

भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियाँ जल-कूटनीति को द्विपक्षीय संबंधों का एक संवेदनशील विषय बनाती हैं। कृषि, पेयजल, मत्स्य पालन, नदी-परिवहन और पारिस्थितिक संतुलन के लिए जल की उपलब्धता दोनों देशों के लिए महत्त्वपूर्ण है। गंगा जल-साझाकरण समझौता इस क्षेत्र में सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जबकि तीस्ता जल-बँटवारे का प्रश्न अब भी विवादित बना हुआ है।

जल-विवाद केवल तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं है। इसका संबंध खाद्य सुरक्षा, स्थानीय आजीविका, पर्यावरणीय स्थिरता और दोनों देशों में जनमत से भी है। Obaidullah और Howlader (2025) भारत-बांग्लादेश जल-विवाद के भू-राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

रेखांकित करते हैं। नदी-जल प्रबंधन के प्रश्नों का समाधान केवल राजनयिक वार्ता से नहीं, बल्कि साझा आँकड़ों, वैज्ञानिक आकलन और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही संभव है।

गंगा जल-साझाकरण संधि की निर्धारित अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। इसलिए संधि के भविष्य पर संवाद, बदलती जलवायु परिस्थितियों का आकलन और जल-प्रवाह से जुड़े आँकड़ों का आदान-प्रदान समय-संवेदनशील प्राथमिकताएँ हैं (Rupen, 2026)। किसी नए या संशोधित प्रबंध में मौसमी प्रवाह, सूखे और बाढ़ के जोखिम, पर्यावरणीय आवश्यकताओं तथा दोनों देशों के संबंधित क्षेत्रों की आजीविका को ध्यान में रखना चाहिए।

सीमा प्रबंधन भी द्विपक्षीय विश्वास से सीधे जुड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी साझा सीमा पर तस्करी, अनियमित आवागमन और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ सीमा पर होने वाली हिंसक घटनाएँ भी चिंता का विषय रही हैं। सीमा-सुरक्षा की आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी यह आवश्यक है कि कार्यवाही पारदर्शी, अनुपातिक और मानवीय मानकों के अनुरूप हो। नियमित सीमा-समन्वय, स्थानीय प्रशासन के बीच संवाद और घटनाओं की समयबद्ध जाँच से तनाव को कम किया जा सकता है।

जल और सीमा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिक महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि इनका प्रभाव सीधे स्थानीय समुदायों पर पड़ता है। यदि इन प्रश्नों पर पर्याप्त संवाद नहीं होता, तो स्थानीय असंतोष व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए तकनीकी सहयोग और राजनीतिक संवाद को एक-दूसरे का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक मानना चाहिए।

VI. राजनीतिक परिवर्तन और द्विपक्षीय विश्वास

अगस्त 2024 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में राजनीतिक विश्वास का प्रश्न अधिक प्रमुख हो गया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के संबंधों पर घरेलू राजनीतिक बहस, सार्वजनिक धारणाओं और कूटनीतिक प्राथमिकताओं का प्रभाव दिखाई दिया। इस स्थिति में भारत के लिए आवश्यक है कि वह बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ व्यावहारिक संवाद बनाए रखे। बांग्लादेश के लिए भी भारत के साथ संबंधों को केवल पूर्ववर्ती राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में देखने के बजाय दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे बढ़ाना उपयोगी होगा।

बांग्लादेश में अगस्त 2024 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार का गठन द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया अवसर लेकर आया (Lok Sabha Secretariat, 2026)। भारत ने नई सरकार के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की और प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया। हालाँकि, राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव अपने आप द्विपक्षीय मतभेदों को समाप्त नहीं करता। संबंधों में वास्तविक सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश आपसी विश्वास बहाल करने और व्यापार, जल-साझाकरण तथा सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर कितनी ठोस प्रगति करते हैं।

Ranjan (2024) ने शेख हसीना के बाद की परिस्थितियों में भारत के संभावित विकल्पों पर चर्चा की है। Palit (2024) का विश्लेषण इस बात पर ध्यान देता है कि राजनीतिक संकट द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है। इन विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि राजनीतिक तनाव

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

और आर्थिक परस्पर निर्भरता एक साथ मौजूद रह सकते हैं; इसलिए किसी एक क्षेत्र में तनाव का अर्थ यह नहीं कि सभी सहयोगात्मक व्यवस्थाएँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए नियमित उच्चस्तरीय संवाद के साथ-साथ विदेश मंत्रालयों, सीमा-सुरक्षा संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन के बीच संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। संवाद को केवल संकट के समय सक्रिय करने के बजाय उसे निरंतर संस्थागत प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन होने पर भी सहयोग के मूल ढाँचे को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

जन-से-जन संपर्क भी इसी प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों और पारिवारिक संपर्कों के माध्यम से दोनों समाजों के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं। वीज़ा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, वैध आवागमन की सुविधा और गलत सूचनाओं के प्रति जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद राजनीतिक अविश्वास को कम करने में योगदान दे सकते हैं।

राजनीतिक विश्वास का निर्माण केवल सरकारी स्तर पर किए गए समझौतों से संभव नहीं है। इसके लिए दोनों देशों में सार्वजनिक विमर्श के प्रति संवेदनशीलता, एक-दूसरे की घरेलू परिस्थितियों की समझ और विवादास्पद मुद्दों पर संयमित कूटनीतिक व्यवहार भी आवश्यक है। किसी एक राजनीतिक दल या नेतृत्व के साथ संबंधों को संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का पर्याय मानना दीर्घकालीन सहयोग के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।

VII. भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए रणनीतिक विकल्प

भारत-बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसी एक देश पर नहीं डाली जा सकती। भारत को जल-साझाकरण, सीमा प्रबंधन और व्यापार से जुड़े लंबित प्रश्नों पर संवेदनशीलता के साथ प्रगति करनी चाहिए। दूसरी ओर, बांग्लादेश को भी भारत की सुरक्षा-संबंधी चिंताओं पर सहयोग, सीमा-पार अपराधों की रोकथाम और द्विपक्षीय समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दोनों देशों के बीच विश्वास तभी मजबूत होगा, जब राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सहयोग को व्यावहारिक रूप दिया जाएगा। बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में भारत-बांग्लादेश संबंधों को स्थिर बनाने के लिए कुछ प्राथमिकताएँ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

पहली प्राथमिकता संस्थागत संवाद को मजबूत करना है। राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बावजूद संयुक्त आयोगों, सीमा-समन्वय तंत्रों, व्यापार वार्ताओं और नदी-जल संबंधी संस्थाओं की बैठकें नियमित होनी चाहिए। इससे विवादों का समाधान केवल राजनीतिक वक्तव्यों या तात्कालिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहेगा।

दूसरी प्राथमिकता आर्थिक सहयोग को अधिक संतुलित बनाना है। भारत बांग्लादेशी उत्पादों के लिए बाजार पहुँच और सीमा-पार व्यापार की प्रक्रियाओं में सुधार कर सकता है। दोनों देश उत्पादन-आधारित सहयोग, औद्योगिक निवेश और आपूर्ति शृंखलाओं के विकास पर काम कर सकते हैं। ऐसे सहयोग से व्यापार के लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित होंगे और आर्थिक परस्पर निर्भरता को राजनीतिक समर्थन मिलेगा।

तीसरी प्राथमिकता जल-कूटनीति को वैज्ञानिक तथा जलवायु-संवेदनशील बनाना है। नदी-प्रवाह से संबंधित साझा आँकड़ों का आदान-प्रदान, संयुक्त तकनीकी अध्ययन, बाढ़ पूर्वानुमान और सूखे की स्थिति में समन्वित प्रबंधन सहयोग के ठोस क्षेत्र हैं। गंगा जल-साझाकरण संधि की आगामी अवधि को देखते हुए दोनों देशों को समय रहते संवाद शुरू करना चाहिए, ताकि किसी भी अंतरिम स्थिति से अनिश्चितता या राजनीतिक तनाव न बढ़े।

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

चौथी प्राथमिकता चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों को यथार्थवादी दृष्टि से समझना है। भारत को बांग्लादेश के आर्थिक विकास और विदेश नीति के विकल्पों को स्वीकार करते हुए अपनी वैध सुरक्षा चिंताओं पर पारदर्शी संवाद करना चाहिए। बांग्लादेश को भी विभिन्न बाहरी साझेदारों के साथ सहयोग करते समय आर्थिक व्यवहार्यता, ऋण जोखिम, तकनीकी निर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता का आकलन करना चाहिए। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को शून्य-योग दृष्टिकोण से देखने के बजाय सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना दोनों के हित में होगा।

पाँचवीं प्राथमिकता सीमा-सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। तस्करी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के साथ-साथ सीमा पर होने वाली हिंसक घटनाओं की जाँच, स्थानीय समुदायों की आजीविका और वैध आवागमन को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए। सुरक्षा सहयोग तभी टिकाऊ होगा जब सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों का विश्वास भी बना रहे।

बांग्लादेश का चीन सहित अन्य देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग करना उसके स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी निर्णयों का हिस्सा है। हालाँकि, इस सहयोग के क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को बांग्लादेश पर किसी एक देश को चुनने का दबाव डालने के बजाय व्यापार, संपर्क, ऊर्जा और विकास के क्षेत्रों में बेहतर सहयोग के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। वहीं, बांग्लादेश से भी अपेक्षा है कि वह भारत के साथ अपनी भौगोलिक निकटता, आर्थिक परस्पर निर्भरता और साझा सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास और सहयोग बनाए रखने का प्रयास करे। इस प्रकार, संबंधों में स्थिरता दोनों देशों की पारस्परिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक पहल पर निर्भर करती है।

अंततः, दोनों देशों को जन-से-जन संबंधों को राजनीतिक उतार-चढ़ाव से बचाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े नियमित संपर्क द्विपक्षीय संबंधों के सामाजिक आधार को मजबूत करते हैं। यह आधार किसी एक राजनीतिक नेतृत्व या किसी एक रणनीतिक परियोजना पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

VIII. निष्कर्ष

भारत-बांग्लादेश संबंधों की वर्तमान स्थिति सहयोग और प्रतिस्पर्धा, आर्थिक परस्पर निर्भरता और राजनीतिक अविश्वास तथा भौगोलिक निकटता और रणनीतिक विविधीकरण की आकांक्षाओं के बीच विकसित हो रही है। चीन की बढ़ती उपस्थिति इस समीकरण को प्रभावित करती है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की दिशा केवल भारत-चीन प्रतिस्पर्धा से निर्धारित नहीं होती। व्यापार, जल-संसाधन, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा और जन-से-जन संपर्क जैसे प्रत्यक्ष मुद्दे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को समान रूप से प्रभावित करते हैं।

इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष है कि दीर्घकालीन स्थिरता के लिए दोनों देशों को अपने मतभेदों को संस्थागत संवाद के माध्यम से प्रबंधित करना होगा। भारत के लिए बांग्लादेश के साथ आर्थिक सहयोग को अधिक पारस्परिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाना आवश्यक है। बांग्लादेश के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ संबंध विकसित करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों का संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। जल-साझाकरण, सीमा प्रबंधन और व्यापार जैसे प्रश्नों पर ठोस प्रगति राजनीतिक विश्वास को मजबूत करने में सहायता कर सकती है।

अतः भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य किसी एक बाहरी शक्ति की उपस्थिति या किसी एक राजनीतिक परिवर्तन से तय नहीं होगा। इसकी दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश पारस्परिक हितों, समान सम्मान और व्यावहारिक सहयोग को किस हद तक निरंतर संस्थागत रूप दे पाते हैं।

International Journal of Science and Social Science Research
ISSN: 2583-7877 Peer Reviewed & Refereed Journal
Page No: 198-205 DOI: https://doi.org/10.63671/ijsssr.v4i3.660
Volume: 4 | Issue: 3
October-December 2026

संदर्भ-सूची

1. AFP. (2024, November 12). *Bangladesh has not 'handed over' St Martin's island to US: Govt officials*. https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.36LN6EH
2. Al Amin. (2025). Sino-Indian rivalry in Indo-Pacific and Bangladesh's geo-strategic hedging in response to its security threats. *Discover Global Society, 3*, Article 15. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00144-1
3. Anadolu Agency. (2026, September 10). *Bangladesh rules out Premier Rahman's BRICS participation in India*. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-rules-out-premier-rahmans-brics-participation-in-india/4053451
4. Datta, S. (2008). Bangladesh's relations with China and India: A comparative study. *Strategic Analysis, 32*(5), 755–772. https://doi.org/10.1080/09700160802309134
5. Lok Sabha Secretariat. (2026, February 17). *Lok Sabha Speaker represents India at swearing-in ceremony of Bangladesh Prime Minister Mr. Tarique Rahman*. Press Information Bureau, Government of India. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2229289&lang=1&reg=3
6. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. (2024, December 3). *Import and export with Bangladesh* (Lok Sabha Unstarred Question No. 1233). https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2024/12/LS-USQ-No.1233-dated.-03.12.2024.pdf
7. Obaidullah, M., & Howlader, M. R. (2025). Assessing geopolitical and socio-economic consequences of India-Bangladesh water disputes. *Discover Global Society, 3*, Article 1. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00137-0
8. Palit, A. (2024, August 13). *Bangladesh crisis: Implications for India-Bangladesh economic ties*. Institute of South Asian Studies, National University of Singapore. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/bangladesh-crisis-implications-for-india-bangladesh-economic-ties/
9. Rahman, M. A. (2025). Bangladesh's relations with India and China: The regional context and strategies for Bangladesh. *BIISS Journal, 46*(2), 247–272. https://doi.org/10.56888/biiss-journal.v46i2.a920
10. Ranjan, A. (2024, August 12). *India's options in post-Hasina Bangladesh*. Institute of South Asian Studies, National University of Singapore. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/indias-options-in-post-hasina-bangladesh/
11. Rupen, A. (2026, July 27). *A climate in crisis, a treaty in question: The 2026 Ganga Water Treaty deadline*. Indian Council of World Affairs. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=1&lid=9047&ls_id=14711